

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण के लिए अर्जियों को अग्रप्रेषित किया जाना

2337. श्री अनन्तराम जायसवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और प्रशिक्षण हेतु उनकी अर्जियों को नियमानुसार समय पर अग्रप्रेषित नहीं करते ; यदि हां, तो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा इस प्रकार का नकारात्मक रुख अपनाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार को ऐसी कितनी अर्जियां प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितनी अर्जियों को समय पर अग्रप्रेषित किया और शेष अर्जियों को समय पर अग्रप्रेषित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में इस सेवा के अधिकारियों की अर्जियों को समय पर अग्रप्रेषित किया जाए ; यदि हां, तो किस प्रकार से और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोबर्धन) : (क) से (ग) प्रतिनियुक्ति तथा प्रशिक्षण हेतु भारतीय सांख्यिकीय सेवा (भा०सा० से०) अधिकारियों के आवेदन पत्रों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू हिदायतों के अनुसार कार्रवाई की जाती है । ऐसे आवेदन पत्र अग्रप्रेषित करने के अधिकार सांख्यिकी विभाग जो कि भारतीय सांख्यिकीय सेवा के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण है, में केन्द्रीयकृत नहीं हैं अपितु उन अधिकारियों के संबन्ध में छोड़कर जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, ये अधिकार उन संगठनों को सौंपे गये हैं जिनमें वे कार्य कर रहे हैं । तथापि, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करनी होती है । जिसके लिये कुछ निर्धारित व्यूरे

प्रस्तुत करना अपेक्षित है । जब ये प्राप्त नहीं होते हैं अथवा अपूर्ण रूप में प्राप्त होते हैं । तो यह मामला संबंधित संगठन को वापिस भेजा जाता है । इसके होते हुए भी, इस संबन्ध में विलम्ब से बचने के लिये सभी प्रयास किये जाते हैं ।

Decline of Standards of Education in the Universities

2338. SHRI KRISHNA IKUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) when a study, if any, was made by Government to know the decline in the standards of education in universities in the country.

(b) what are the areas of study made;

(c) What is the *outcome* of the study, stating the areas of the said decline and the causes notified therefor; and

(d) what corrective measures have been taken/proposed to be taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) to (d) I A thorough review of the education system in the country was undertaken at the time of formulation of National Policy on Education—1986. Several initiatives have been taken in pursuance of the National Policy on Education and Programme of Action to improve the standard of education in institutions of higher learning. Some of the major steps taken in this regard are:

— Revision of pay-scale for college and university teachers from 1. 1. 1986. Opportunities for training and career advancement for teachers. All-India Eligibility Test introduced to attract best talent in the teaching profession.